through imports; (iii) restraining undue expansion in money supply; (iv) curbing anti-social activities such as hoarding and black-marketing and (v) increasing production. The price situation is being kept under constant watch and further suitable measures will be taken as and when necessary.

Anticipated Losses of Public Sector Undertakings

748. SHRI CHHANGUR RAM: SHRI RASHEED MASOOD: SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

SHRI RAM VILAS PASWAN: PROF. AJIT KUMAR MEHTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the public sector undertakings are likely to incur heavy losses during the current financial year as compared to the losses suffered by them during the earlier years;
- (b) if so, the losses anticipated by the public sector undertakings (giving names thereof) during the current financial year as compared to the losses suffered by them during the last two years;
- (c) whether Government have made any assessment with regard to the functioning of these public sector undertakings; and
- (d) if answer to part (c) be in the affirmative, the result thereof and the steps taken/proposed to be taken by the Government to minimise the losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) A reliable estimate of the 1980-81 public sector operating results will be possible only by about October, 1981. In the 1980-81 budget estimates, among the principal public sector enterprises, the Fertilizer and Coal groups may be expected to reduce their losses

while the Steel Group may end with a reduced profit as compared to 79-80. The Petrochemicals, Shipping and Engineering groups also may be expected to do better. On the basis of a quick survey conducted by the Bureau of Public Enterprises for the quarter ending 30th June, 1980, all the public enterprises put together have suffered a net loss estimated approximately at Rs. 161 crores after providing income-tax of Rs. 38 crores by the profit-earning enterprises.

- (b) A statement showing the losses incurred by the losing enterprises in the first quarter of 1980-81 as well as in the previous two years is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1381/80]. The losses for the first quarter are provisionally estimated.
- (c) and (d). The Administrative Ministries constantly review the performance of the undertakings under their control for taking corrective steps wherever necessary. Recently Government have appointed an Expert Committee under the Chairmanship of Shri Mohammad Fazal, Member of the Planning Commission, to examine the performance in respect of major Enterprises in the Steel, Engineering, Coal, Chemicals and Fertilizers and Shipping sectors. The Committee's work is in progress.

Privileges and Perks enjoyed by Vice-President of Super Bazars

749. SHRI CHHANGUR RAM. Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

- (a) whether Government are aware of the privileges and perks being enjoyed by the Vice-President of the Super Bazars over and above the normal entitlement;
- (b) if so, whether Government have made any inquiry into the circumstances under which the extra privileges have been provided to the Vice-President of Super Bazars; and
- (c) the expenditure incurred by the Super Bazar/authority concerned in providing extra privileges?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY) (a) to (c). It is presumed that the Question relates to the Super Bazar, Delhi which is under the administrative control of this Ministry. Vice-President of the Super Bazar, Delhi is not enjoying any privileges and perks over and above the normal entitlement.

विदेशी मुद्रा रिजर्व में वृद्धि करने के उपाय

750 श्री विलास मुत्तेमबार : श्रीमती कृष्णा साही : श्री जी ० एम० यनातवाला :

क्या वित्त मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि

- (क) देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में कमी भ्राने से संबंधित समाचारपवों मे प्रकाशित समाचारों में क्या सच्चाई है :
- (ख) सही स्थिति दर्शाने वाले वास्त-विक भ्रांकडे क्या है , ग्रौर
- (ग) विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में कमी के क्या कारण है तथा उसमें वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

धित्त मंत्रारूय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) :

(क) ग्रौर (ख) : मार्च 1980 के **अन्त में सोने ग्रांर एस० डी० आर० को** छोड़ कर भारत का विदेशी मुद्रा भडार 5163.66 करोड़ रुपये का था जो 7 नवम्बर, 1980 को 4965.72 करोड़ रुपये का रह गया, भ्रर्थात् इस में 197.94 करोड़ रुपये की कमी हो गई। यह राशि ग्रस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि (ट्रस्ट फंड) ग्रीर प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा (कम्पेन्सेंटरी फाइनेंसिंग फेसिलिटि). से की जाने वाली कुल मिला कर लगभग 8 15 करोड़ रुपये की निकासियों को हिसाब में लेने के बाद म्रांकी गई है।

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में होने बाले परिवर्तन ग्रन्य देशों के साथ भारत के लेनदेनों का निवल परिणाम होते हैं, जिनका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शोधन शेष के ग्रांकड़ों का संचलन कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा । किन्तु स्थूल संकेतों के ग्रनुसार विदेशी मुद्रा भंडार (सोने ग्रौर एस० डी० ग्रार० को छोड़ कर) में कमी मुख्य रूप से बहुत बड़े व्यापारिक घाटे के कारण हुई है । यह घाटा एक ग्रोर मध्यवर्ती वस्तुग्रों ग्रीर कच्चे माल, खाद्य तेलों जैसी श्राम उपयोगी की वस्तुम्रों के म्रधिक म्रायात, कच्चे तेल ग्रौर पेट्रोलियम उर्वरकों, लौह ग्रौर ग्रलौह धातुग्रों ग्रादि की श्रन्तर्राष्ट्रीय कीमतो मे वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्रायात बिल के काफी बढ़ जाने श्रौर दूसरी निर्यातों के विकास की श्रपेक्षाकृत धीमी गति होने के कारण हम्रा है।

सरकार विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने ग्रौर उसके भावी विकास के मार्ग मे ग्राने वाली रूकावटो को दूर करने के लिए कई उपाय करनी रही है जिनमे ये शागिल हैं.

- 1. कोयला, बिजली, रेल, जैसे मुख्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन ग्रोर सामान्य मूलभूत ढांचे में सुधार के उपाय करना ताकि ग्रौद्योगिक क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके श्रौर श्रान्तरिक उत्पादन में सुधार करना तथा ग्रायात की ग्रावश्यकताग्रों को भी यथासंभव कम करना ।
- 2. निर्यात की क्षमता वाली मदों के उत्पादन पर जोर देने जैसे निर्यात को